3 भरत सोनी को बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान

5 नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा

7 सेवानिवृत्तिः अनुभवी पारी का आगाज

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 28 प्रति सोमवार, 17 नवंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

बिहार में एनडीए की भारी जीत, महागठबंधन की महापराजय

एनडीए : 202 (2020 में 125 सीटें)

कुल सीट- 243
बहुमत के लिए - 122

महागठबंधन : 35 (2020 में 110 सीटें)

भाजपा	जदयू	लोजपा-R	हम	रालोमो
89(+15)	85(+42)	19(+18)	05(+01)	04(+04)
वोट शेयर (20.08%)	वोट शेयर (19.25%)	वोट शेयर (04.97%)	वोट शेयर (उपलब्ध नहीं)	वोट शेयर (उपलब्ध नहीं)
101 सीट पर लड़ी	101 सीट पर लड़ी	29 सीट पर लड़ी	06 सीट पर लड़ी	06 सीट पर लड़ी

राजद	कांग्रेस	वामदल	वीआईपी	आईआईपी
25(-50)	06(-13)	03(-09)	00(-04)	01(+01)
वोट शेयर (23.00%)	वोट शेयर (08.71%)	वोट शेयर (04.28%)	वोट शेयर (उपलब्ध नहीं)	वोट शेयर (उपलब्ध नहीं)
144 सीट पर लड़ी	61 सीट पर लड़ी	33 सीट पर लड़ी	15 सीट पर लड़ी	03 सीट पर लड़ी

(विस्तृत पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश भाजपा में बदलती कार्यशैली, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नया प्रयोग

वरिष्ठ हारे नेताओं को मिलेगा निगम–मंडलों में स्थान

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश भाजपा संगठन में इन दिनों एक महत्वपूर्ण आंतरिक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करते हुए संगठनात्मक समरसता और पार्टी कैडर के मनोबल को मजबूत करने की दिशा में एक नया प्रयोग शुरू किया है। यह प्रयोग संगठन के भीतर लंबे समय से महसूस की जा रही आपसी रंजिश, मनमुटाव और उपेक्षित भाव को थामने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद अब भाजपा प्रदेश में उन वरिष्ठ नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों को निगम-मंडलों में स्थान देने की तैयारी में है, जो पिछले चुनावी परिणामों या भीतरघात की परिस्थितियों के कारण राजनीतिक मुख्यधारा से दूर होते चले गए थे।

वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा पर रोक की कोशिश

पार्टी सूत्र बताते हैं कि बीते कुछ महीनों में भाजपा के भीतर एक वर्ग ऐसा था जो लगातार उपेक्षा, असंतोष और आंतरिक खींचतान को लेकर नाराज चल रहा था। कई नेता चुनाव हारने के बाद संगठनात्मक जिम्मेदारियों से भी दूर कर दिए गए, जिससे वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से किनारा कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया कि ऐसे नेताओं को दोबारा सक्रिय राजनीति में लाने और उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए them निगम-मंडलों में जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी।

पार्टी की अंदरूनी एकता पर फोकस

हेमंत खंडेलवाल के इस कदम को भाजपा के भीतर चल रहे गुटबाजी को कम करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। लंबे समय से पार्टी में अलग-अलग धड़ों के बीच संवादहीनता और नाराजगी की बातें सामने आती रही हैं। अब संगठन का मानना है कि यदि वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो इससे दो लाभ मिलेंगे। एकता का संदेश जाएगा, चुनावी रणनीति में विविध अनुभव के लोग फिर से सक्रिय रूप से योगदान देंगे। पार्टी के अंदरूनी जानकारों का कहना है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को साफ संकेत दे दिया है कि 2028 की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और इसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता साथ लेकर चलना जरूरी है।

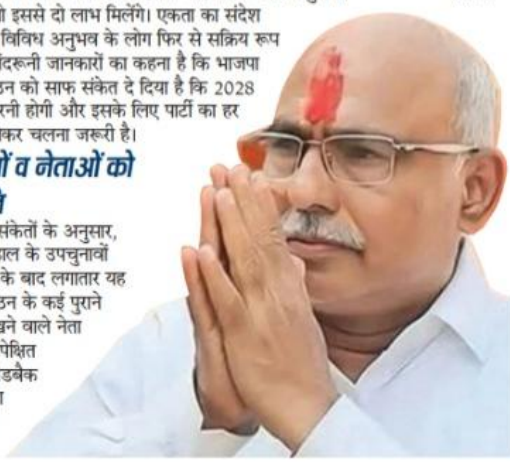

निराश कार्यकर्ताओं व नेताओं को साधने की रणनीति

पार्टी के अंदर से प्राप्त संकेतों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल हाल के उपचुनावों और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लगातार यह फीडबैक ले रहे थे कि संगठन के कई पुराने चेहरे और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेता किसी न किसी कारण से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी फीडबैक के आधार पर नए प्रयोग का खाका तैयार किया गया है।

(शेष पेज 2 पर)

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की धरती सदियों से वीरता, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं की साक्षी रही है। आदिवासी परंपराओं ने इस प्रदेश के इतिहास को केवल संवारा ही नहीं बल्कि उसे बल, दिशा और पहचान भी दी है। जहां पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय चेतना का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में सोनाखान के वीर नारायण सिंह ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देकर आदिवासी प्रतिरोध की परंपरा को अमर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हीं ऐतिहासिक भावनाओं, अस्मिता और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के इतिहास में पहला ऐसा निर्णय लिया जिसने छत्तीसगढ़ को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दी नवा रायपुर में आधुनिक डिजिटल जनजातीय संग्रहालय की स्थापना। (शेष पेज 2 पर)

बिहार में एनडीए की भारी जीत, महागठबंधन की महापराजय

-संवाददाता

जगत प्रवाह. पटना। देवरीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। एनडीए को उम्मीद से ज्यादा जनसमर्थन मिला है और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं महागठबंधन को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। निश्चित ही इस जीत ने एनडीए को और मजबूत किया है। जो आने वाले समय में केन्द्र की राजनीति में भी फायदेमंद साबित होगा। राज्य में जश्न का माहौल है। जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। बिहार की जनता ने NDA को प्रचंड बहुमत देकर वोट चोरी के कांग्रेस के मुद्दे को हवा में उड़ा दिया है, बिहार की जनता ने कांग्रेस पर खासकर राहुल गांधी पर भरोसा नहीं किया, तेजस्वी यादव के नौकरियों के वादों सहित अन्य वादों पर भरोसा नहीं किया और राहुल और उनकी दोस्ती को नकार दिया और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा कर फिर से उन्हें सरकार बनाने का मौका दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर बिहार की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने X पर लिखा, बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने X पर लिखा- यह 'विकसित बिहार' में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएँ, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ 'Politics of performance' के आधार पर जनादेश देती है।

छत्तीसगढ़ में आदिवासी अस्मिता, स्मृति और विज्ञान का नया संगम

(पेज 1 का शेष)

आदिवासी गौरव की पुनर्स्थापना का संकल्प

मुख्यमंत्री साय का यह निर्णय केवल एक भवन निर्माण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक आंदोलन का रूप है। वे मानते हैं कि आदिवासी इतिहास को केवल किताबों में सीमित रखने से उसकी व्यापकता और समृद्धि घटती है। इसलिए एक ऐसे संग्रहालय की आवश्यकता थी जो इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करे, जहां नई पीढ़ी यह देख सके कि आजादी का संघर्ष केवल मैदानों में नहीं, जंगलों में भी लड़ा गया था। नवा रायपुर के सेक्टर- 24 में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बना यह डिजिटल संग्रहालय देश का पहला ऐसा आधुनिक केंद्र है, जिसमें इतिहास, विज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं यह भी इस परियोजना की राष्ट्रीय महत्ता को सिद्ध करता है।

वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का गौरव

संग्रहालय की आत्मा है वीर नारायण सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और अंततः शहीद हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें पुनः छत्तीसगढ़ की चेतना के केंद्र में स्थापित किया है। संग्रहालय में उनका भव्य स्मारक न केवल इतिहास की धरोहर है बल्कि भावी पीढ़ी को यह सिखाने का माध्यम भी है कि आदिवासी समाज केवल संस्कृति का वाहक नहीं, बल्कि संघर्ष का अग्रदूत भी रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की जनजातीय नीतियों का विस्तार

मुख्यमंत्री का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न को आगे बढ़ाता है, जिसने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर आदिवासी इतिहास को राष्ट्रीय विमर्श में केंद्रित किया। इसके बाद देश में दो बड़े अभियान शुरू किए गए पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं।

इतिहास को जीवंत करती तकनीक

संग्रहालय का सबसे प्रेरणादायक आयाम है वह सेक्शन जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों को नई तकनीक के साथ दर्शाया गया है। ये प्रस्तुतियाँ केवल ऐतिहासिक जानकारी नहीं देतीं, बल्कि दर्शकों को उस समय की वैचारिक और भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव भी कराती हैं। डिजिटल संग्रहालय छत्तीसगढ़ के इतिहास का भविष्य। यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम है वीएफएक्स आधारित प्रस्तुतीकरण 3D प्रोजेक्शन डिजिटल स्क्रीन, QR कोड आधारित मोबाइल इंटरफेस

मोशन फिल्मों के रूप में कहानियाँ

1,400 वर्ष पुराने साल-सेमर-साजा वृक्ष की प्रतिकृति आदिवासी कला से सजा फर्श, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सरगुजा के कलाकारों द्वारा नक्काशीदार पैनल और आदिवासी सशक्तिकरण की मूर्तियाँ इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक केंद्र बनाती हैं। आदिवासी संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनता छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे छत्तीसगढ़ को केवल संसाधनों के राज्य के रूप में नहीं, बल्कि विरासत, इतिहास और जनजातीय संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ का यह पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय न केवल राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का दर्पण है, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण भी है। यह केवल भवन नहीं, बल्कि एक जीवंत संकल्प है- आदिवासी गाथाओं को सम्मान, पहचान और वैश्विक मंच प्रदान करने का। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह पहल आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक पर्यटन, नवाचार और सामाजिक समृद्धि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और यही है एक समर्पित नेतृत्व की पहचान।

मध्यप्रदेश भाजपा में बदलती कार्यशैली, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नया प्रयोग

(पेज 1 का शेष)

बताया जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल के कार्यालय में पिछले कुछ हफ्तों में निराश कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार संपर्क और संवाद बढ़ा है। सूत्र बताते हैं कि जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद संगठन के प्रति निष्ठा दिखाई, या जो विभिन्न कारणों से राजनीतिक मुख्यधारा से दूर हो गए थे, और जो पार्टी के भीतर खींचतान का हिस्सा बन गए थे, उन्हें अब निगम-मंडलों में महत्वपूर्ण दायित्व देकर सक्रिय किया जाएगा।

केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट संकेतः हर वर्ग को प्रतिनिधित्व

केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद यह तय माना जा रहा है कि आगामी सूची में युवा और वरिष्ठ दोनों प्रकार के नेताओं को जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण निगमों में ऐसे नेताओं की तैनाती होगी जो पहले मंत्री रहे हैं, जबकि कुछ बोर्डों और आयोगों में उन नेताओं की नियुक्ति होगी जो सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव के साथ आते हैं। यह कदम राज्य में भाजपा संगठन की पकड़ और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की गंभीर रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

2028 की तैयारी के लिए संगठन का पुनर्गठन

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व 2028 की सत्ता-परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठन की संरचना मजबूत करने में जुट गया है। हेमंत खंडेलवाल की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैडर आधारित पार्टी में असंतोष को अनदेखा करना जोखिम भरा होता है और भाजपा जैसी व्यापक संगठनात्मक संरचना में हर स्तर के कार्यकर्ता और नेता की भूमिका अहम होती है। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी जिला अध्यक्षों, मोर्चों और प्रकोष्ठों में भी आंशिक फेरबदल कर सकती है ताकि संगठन और मजबूत हो सके।

अंदरूनी रंजिशों पर रोक का प्रयास

पार्टी के भीतर एक लंबे समय से चर्चा थी कि कुछ नेता अपने-अपने गुटों को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे पार्टी की छवि और कार्यशैली प्रभावित हो रही है। अब खंडेलवाल द्वारा शुरू किया गया यह प्रयोग पार्टी के भीतर यह संदेश देने में सफल माना जा रहा है कि "पार्टी में हर किसी को अवसर मिलेगा, बशर्ते वह संगठन के प्रति निष्ठा रखता हो और सक्रिय रूप से काम करने को तैयार हो।

जल्द जारी होगी सूची, कई दिग्गजों के नाम शामिल होने की संभावना

सूत्रों के मुताबिक, निगम मंडलों की प्रस्तावित सूची अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। संभावना है कि सूची में पूर्व विधायकों, चुनाव हार चुके वरिष्ठ नेताओं और लंबे समय से सक्रिय पार्टी पदाधिकारियों को अहम स्थान दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सूची का मसौदा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है और किसी भी समय इसे जारी किया जा सकता है। मध्यप्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा की जा रही यह पहल संगठनात्मक सुधार और भीतर की नाराजगी को दूर करने का गंभीर प्रयास है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इससे न केवल पार्टी की आंतरिक एकता मजबूत होगी बल्कि आने वाली चुनावी रणनीतियों में भी भाजपा को लाभ मिलेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हेमंत खंडेलवाल का यह कदम भाजपा की उस कार्यशैली की वापसी है जहाँ संगठन और सरकार दोनों समानांतर रूप से चलते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं।

भरत सोनी को मिला बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भरत सोनी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छेदीलाल सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया। साथ ही अनेक वरिष्ठ जन मौजूद रहे सोनी के सम्मानित होने पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रक केसी यादव प्रदेश अध्यक्ष दलजीत सिंह गुरूदता संरक्षक उपेन्द्र सिंह यादव, प्रदेश महासचिव प्रमोद बरसले, प्रदेश सह सचिव दिनेश जागलवा, वकील खान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार डीके शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, राजेन्द्र कोठारी, कपिल जागलवा, फिरोज शाह, नीलेश जागलवा, राम चन्द्र गिनारे, अशोक मुंदड़ा, अभिषेक भिलाला, मुकेश परदेशी, शेर सिंह उईके, मनोज कुशवाह आदि अनेक पत्रकारों ने सोनी को बधाई दी।

एम्स भोपाल ने फिर रचा इतिहास : तीसरा हृदय प्रत्यारोपण सफल

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर नई ऊँचाइयाँ स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में संस्थान ने तीसरा हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक पूरा कर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि न केवल एम्स भोपाल की मजबूत चिकित्सा क्षमता को दर्शाती है, बल्कि उन मरीजों और परिवारों के लिए आशा की नई किरण भी है जिन्हें हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। यह हृदय एक ब्रेन-डेड मरीज से प्राप्त किया गया था। उनके परिजनों ने दूसरों को जीवनदान देने की भावना से अंगदान के लिए स्वीकृति दी, जिससे यह प्रत्यारोपण संभव हो पाया। यह कदम समाज में अंग दान के महत्व और मानवीय भावना को उजागर करता है। प्रत्यारोपण प्रक्रिया एम्स भोपाल की कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) टीम ने पूरी जिम्मेदारी और विशेषज्ञता के साथ संपन्न की। टीम में डॉ. योगेश निवारिया, डॉ. एम किशन, डॉ. सुरेंद्र यादव, डॉ. राहुल शर्मा, डॉ. विक्रम वट्टी और डॉ. आदित्य सिरोही शामिल थे। इसके अतिरिक्त कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. भूषण शाह और डॉ. सुदेश प्रजापति ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्डियक एनेस्थेटिस्ट टीम ने इस जटिल प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भूमिका निभाई। इस टीम का मार्गदर्शन डॉ. वैशाली वंडेस्कर ने किया और इसका नेतृत्व डॉ. पूजा, डॉ. हरीश और डॉ. नागभूषणम कर रहे थे। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ प्रो. (डॉ.) माधवानंद कर ने इस सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि डॉक्टरों, मेडिकल टीम और प्रशासन की कठिन मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह तीसरी बार है जब एम्स भोपाल ने हृदय प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उन्होंने अंग दान करने वाले परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका यह निर्णय कई लोगों के लिए जीवनदान साबित होता है।

बाल दिवस पर विदिशा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान, 5,000 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे और समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में तथा समस्त थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में आज 14 नवम्बर 2025 को जिले में बाल दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने एवं उनके सुरक्षित एवं सकारात्मक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। जिले भर के थानों में नाबालिग बच्चों की मैराथन दौड़, थाने में निर्मित बालमित्र कक्ष का भ्रमण, कानूनी जानकारी प्रदान करना, बाल प्रतियोगिताएँ, एवं ऊर्जा हेल्प डेस्क की मदद से बाल सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल दिवस के दौरान बच्चों को पुलिस कार्यप्रणाली, थाने में विभिन्न कक्षों की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं अपराध अनुसंधान की मूलभूत जानकारी से अवगत कराया गया। इस प्रकार बच्चों को कानून एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता प्रदान करते हुए उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रोत्साहित किया गया। जिले के समस्त थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों ने अपने क्षेत्र में बाल दिवस कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया, जिससे बच्चों में उत्साह एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।

जनदर्शन में वूमेन्स सेल्फ डिफेंस ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में वूमेन्स सेल्फ डिफेंस ऑर्गनाइजेशन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे, कुश्ती और ताइक्वांडो जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वेच्छानुदान स्वीकृत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री साय ने संगठन के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों द्वारा रखे गए सुझावों और मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। खिलाड़ियों ने बताया कि वे देश और विदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तथा आगे भी राज्य का नाम और ऊंचा करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और सहयोग की आवश्यकता है। खिलाड़ियों ने खेल उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खिलाड़ियों की भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर यथासंभव सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

सम्पादकीय

बिहार चुनाव में एनडीए को मिले जनमत से मिलेगी सुशासन प्रधान सरकार

बिहार ने एक बार फिर लोकतंत्र के प्रति अपनी परिपक्वता और विवेक का ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालिया चुनाव परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिला स्पष्ट जनमत न केवल राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की जनता अब विकास, सुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। यह जनादेश एक तरह से उस यात्रा की पुनर्पुष्टि है, जिसका आरंभ पिछले डेढ़ दशक में सुशासन के सूत्रों के साथ हुआ था और जिसने बिहार को पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकालकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। इस चुनाव में सबसे उल्लेखनीय यह रहा कि मतदाताओं ने जातिगत समीकरणों, क्षणिक नारों और वादों के बजाय उस नीति-दृष्टि पर भरोसा जताया, जिसने राज्य में वर्षों से स्थायित्व और सुधार की नींव रखी है। एनडीए के पक्ष में आए जनमत की स्पष्टता बताती है कि जनता यह भली-भांति समझ चुकी है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की सरकार और किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। नीतीश कुमार का लंबे समय का प्रशासनिक अनुभव, केंद्र सरकार के सहयोग से लागू अनेक कल्याणकारी योजनाएँ तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं आधारभूत संरचना के विस्तार ने मतदाताओं में विश्वास की भावना मजबूत की है।

बिहार लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, अपराध और अविकास से जूझता रहा है। लेकिन पिछले वर्षों में जिस प्रकार सड़कों, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है, उसने लोगों को यह समझ दी है कि बदलाव संभव है- और नीतियों पर टिके रहने वाली सरकार ही यह बदलाव ला सकती है। हालिया जनमत इसी आशा को पुनः मजबूत करता है। यह विश्वास की पुष्टि है कि विकास को निरंतरता चाहिए, और उसका नेतृत्व ऐसे हाथों में होना चाहिए जो राज्य की सामाजिक विविधता को समझते हों और निर्णयों में स्थिरता रखते हों। एनडीए की जीत इस बात का भी प्रतीक है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बिहार के विकास के लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाएँ चाहे वह गरीब कल्याण से जुड़ी हों, अधोसंरचना से या रोजगार व कौशल विकास से बिहार में प्रभावी रूप से लागू हुई हैं। इन योजनाओं के जमीनी असर ने यह एहसास कराया है कि विकास अब केवल कागजों में नहीं, बल्कि जीवन में उतर सकता है। यही कारण है कि मतदाता ने एनडीए के पक्ष में स्थिर जनादेश देकर राज्य और केंद्र के समन्वय को जारी रखने की इच्छा जताई है। सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र का स्वभाव है, लेकिन विवेकपूर्ण जनमत ही लोकतंत्र की शक्ति है। बिहार के लोगों ने इसी शक्ति का परिचय देते हुए एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे उन नीतियों और नेतृत्व को आगे देखना चाहते हैं जो जाति-वर्ग की खाईयों को पाटकर सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। यह जनादेश इस बात का भी संकेत है कि युवा मतदाता अब विकास, रोजगार और स्वाभिमान को केंद्र में रखकर अपने निर्णय ले रहा है। वह राजनीति के पुराने ढर्रों से दूर होता जा रहा है और नई दृष्टि के साथ बदलाव को स्वीकार कर रहा है।

हालाँकि सुशासन की यह यात्रा अभी अधूरी है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार की आवश्यकता है। इस जनमत ने एनडीए को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वह अपनी उपलब्धियों को आधार बनाकर आने वाले वर्षों में और साहसिक कदम उठाए। नौकरियों, निवेश और औद्योगिक विस्तार की दिशा में ठोस कार्ययोजना राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। साथ ही, सुशासन की असली परीक्षा पारदर्शिता, समयबद्धता और जनता से संवाद में निहित होती है, जिसे बनाए रखना नई सरकार के लिए अनिवार्य होगा। समग्र रूप से देखें तो बिहार के मतदाताओं ने स्थिरता, प्रगति और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए एक परिपक्व राजनीतिक संदेश दिया है। एनडीए के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर यह कि मजबूत जनमत के सहारे वह आगामी वर्षों में बड़े परिवर्तन कर सकती है और चुनौती यह कि इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसे निरंतर गति, पारदर्शिता और जनोन्मुखी प्रशासन का पालन करना होगा।

सियासी गहमागहमी

बिहार चुनाव परिणाम ने तेजस्वी यादव का घमंड किया चूर

बिहार की राजनीति का रंग हमेशा अलग होता है यहाँ हवा की दिशा बदलते ही नेता भी अपने तेवर बदल लेते हैं। मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में नतीजों ने जिस चेहरे का 'पॉलिटिकल मेकओवर' किया है, वह है तेजस्वी यादव। चुनाव से पहले तक जिस आत्मविश्वास को वे "परिवर्तन की लहर" समझ बैठे थे, नतीजों ने उसे एक झटके में "घमंड की फुसफुसाहट" साबित कर दिया। तेजस्वी यादव को भरोसा था कि युवा उन्हें कंधों पर उठाकर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा देंगे। घोषणाएँ इतनी कि मानो चुनाव नहीं, कोई मेगा सेल का उद्घाटन हो रहा हो। रैलियों में उनकी मुस्कान और विपक्ष पर तंज मानो बता रहे हों" अबकी बार बस मैं ही मैं।" लेकिन लोकतंत्र के असल मालिक मतदाताओं ने आखिरकार अहंकार की इस हवा में एक तेज झोंका मारा, और नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी। जनता ने बता दिया कि राजनीति में सिर्फ भाषणों का तापमान नहीं चलता, काम का थर्मामीटर भी देखना पड़ता है। युवा नेतृत्व की छवि अच्छी बात है, पर अनुभव को हवा में उड़ाना जनता के स्वभाव में नहीं। तेजस्वी को यह भी समझ आ गया कि सोशल मीडिया की तालियाँ और मैदान की वोटिंग में बड़ा फर्क होता है। नतीजों के बाद उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल गई वही तेज आवाज अचानक "रीसेट मोड" में चली गई।

MP में जल्द आएगी मुख्य सचिव द्वारा तैयार तबादला सूची

मध्यप्रदेश में मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा तैयार की गई आईएएस अफसरों की तबादला सूची जैसे ही "जल्द जारी होने वाली" श्रेणी में पहुँची, मंत्रालय से लेकर जिलों तक अफसरों में अचानक एक अदृश्य हलचल शुरू हो गई। मानो किसी ने कानों में फुसफुसाकर कह दिया हो "तैयार रहिए, कुर्सी अब आपकी स्थायी संपत्ति नहीं रही।" सूची आने से पहले ही अफसरों ने अलग-अलग योगासन शुरू कर दिए हैं। कुछ "पद्मासन" में अपने वर्तमान जिले को पकड़कर बैठे हैं, तो कुछ "वज्रासन" में मंत्रालय की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारी 'अनिर्णयासन' में हमेशा से ही दक्ष हैं जिन्हें न पता है कि वे कहाँ हैं, न यह कि कहाँ भेजे जाएंगे। मंत्रालय के गलियारों में माहौल ऐसा है जैसे पटवारी परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला हो हर कोई अपनी-अपनी "संभावित कट ऑफ़" पर चर्चा कर रहा है। कुछ तो पहले ही सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश लिखकर तैयार बैठे हैं, ताकि नए जिले में पोस्टिंग मिलते ही कॉपी-पेस्ट करके पोस्ट कर दें।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया।

बिहार का यह परिणाम चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

आजादी की लड़ाई के समय सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले कांग्रेसी, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, सामंती समाज को लोकतंत्र का ककहरा सिखाने वाले और कृषि प्रधान भारत को औद्योगीकरण की राह पर ले जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जन आंदोलन के युग में शुरू हुई

समता पाठक/जगत प्रवाह

नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में दृढ़ता, विकास और सामाजिक न्याय का पर्याय बन गया है। उन्होंने न केवल राज्य को लम्बे समय तक नेतृत्व प्रदान किया है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों और गठबंधनों के माध्यम से उनकी नीतियाँ बिहार को एक नए विकास मॉडल की ओर ले जाने में सहायक रही हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर (पटना जिला), बिहार में हुआ था। उनके पिता, कविराज राम लखन सिंह, एक आयुर्वेदाचार्य और स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनकी माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर में पूरी की और बाद में पटना विज्ञान महाविद्यालय गए। वहाँ उन्होंने विज्ञान एवं गणित में गहरी रुचि ली और अंततः बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्युत अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि ने उन्हें तकनीकी दृष्टिकोण दिया, जिसका बाद में उनके राजनीतिक नेतृत्व में बहुत फायदा हुआ।

नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जन आंदोलन के युग में शुरू हुई। 1970 के दशक के मध्य में वे जेपी आन्दोलन में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। उन्होंने साफ-सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक समानता की विचारधारा को आत्मसात किया। 1985 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उनका उदय तेजी से हुआ जनता दल, बाद में जनता दल (यूनाइटेड) में भूमिका निभाते हुए, उन्होंने केंद्र में भी मंत्री पद संभाला, जैसे रेल, कृषि और परिवहन विभाग में।

नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के कई कार्यकाल देखे हैं। उनकी पहली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 2000 में आई, हालांकि वह ज्यादा लम्बी नहीं रही थी। लेकिन उनसे होने वाली मजबूत और दीर्घकालीन अगुवाई 2005 के बाद हुई, जब वे पुनः मुख्यमंत्री बने और विकास-ऊन्मुख सरकार की नींव रखते हुए "सात निश्चय" जैसी योजनाएँ शुरू कीं। उनकी नीतियों में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी संरचना, सामूहिक सम्मान और सामाजिक सुधार प्रमुख रहे हैं। वे खासकर युवा और पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। नीतीश कुमार अक्सर राजनीतिक संतुलन के मास्टर रहे हैं। उन्होंने अनेक बार अलग-अलग दलों के साथ गठबंधन किया, जैसे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भाजपा और अपनी राजनीति को सक्षम रूप से मोड़ा है। उनके इस कौशल ने उन्हें बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय और प्रभावशाली बनाए रखा है। वे "सुशासन बाबू" के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उनका प्रशासनात्मक दृष्टिकोण अक्सर साफ-सुथरा और जवाबदेह माना जाता है।

नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा और संरचना के स्तर को बेहतर करने पर निरंतर जोर दिया है। उनके शासन में सड़कों, पूलों, बिजली और सामाजिक सेवाओं के विकास की प्रमुख योजनाएँ लागू हुई हैं। हाल ही में उन्होंने आने वाले पाँच वर्ष (2025-2030) में एक करोड़ नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य घोषित किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की आर्थिक गति तेज होगी। उनकी यह योजना यह दिखाती है कि वे बिहार को सिर्फ सत्ता या परंपरा के स्तर पर नहीं, बल्कि स्वरोजगार और कौशल आधारित विकास के दिशा में ले जाना चाहते हैं।

नीतीश कुमार की जीवनशैली सादा और मिलनसार रही है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत व्यावहारिक और जमीनी तौर पर नीतिगत काम किया है। उनके पिता-परिवार की पृष्ठभूमि और ग्रामीण अनुभवों ने उन्हें गरीब-शिक्षा-संवेदनशीलता की ओर झुकाव देने में मदद की। वे अपने परिवार के प्रति भी जुड़े रहे: उनकी पत्नी मंजू सिन्हा (जो अब नहीं रही) और बेटा निशांत उनके निजी जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा चुनौतियों से मुक्त नहीं रही है। गठबंधन राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप और सत्ता रुक-सकने की स्थितियाँ कई बार उनके सामने आई हैं। हालाँकि, उनकी वैचारिक स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें बार-बार राजनीतिक मोर्चे पर लौटने में मदद की है, जिससे वे बिहार की राजनीति में एक स्थायी हस्ती बन सके हैं। आज भी, बिहार के लिए उनका महत्व उतना ही है जितना शुरूआत में था यूं कहें कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक स्थिर स्तंभ हैं, जिनकी सोच भविष्य की दिशा तय करती है।

उत्तराखण्डः निवेश, रोजगार और पर्यटन की नई उड़ान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में "उत्तराखण्ड मॉडल" का स्वरूप

-संवाददाता

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखण्ड ने पिछले दशक में एक ऐसा परिवर्तन देखा है, जिसे अब सिर्फ हिमालयी राज्य की सीमित पहचान से आगे बढ़कर औद्योगिक, पर्यटन व सेवाक्षेत्रों का समेकित मॉडल कहा जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने निवेश को गति देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा हिमालयी पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने का बड़ा प्रयास किया है। इस विश्लेषणात्मक आलेख में हम यह देखेंगे कि कैसे राज्य ने पर्यटन स्थल की पहचान बनाई, कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक दशक के कार्यकाल में विकास की दिशा में कदम बढ़ाए गए, तथा राज्य में शुरू किए गए कुछ प्रमुख नवाचार विशेषकर दुग्ध उत्पादन व गौ-संवर्धन में कैसे रूप ले रहे हैं।

पर्यटन-उद्यमी राज्य का उदय

हिमालयी प्रदेश उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी पहचान रही है – चार धाम-यात्रा, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहचान को निवेश व रोजगार के अवसर में परिवर्तित करने पर खास जोर दिया है। उदाहरण के लिए, राज्य में पिछली कुछ वर्षों में इन बड़े बदलावों का अभिलेख मिल रहा है "लगभग 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पिछले तीन वर्षों में आए"। गतिशील आंकड़े बताते हैं कि लगभग "4,000 यात्री प्रतिदिन हवाई मार्ग से उत्तराखण्ड आ रहे हैं", जबकि राज्य के गठन के समय यह संख्या छह-महीनों में 4,000 थी। धामी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को व्यवस्थित स्वरूप देने हेतु चारधाम ऑथोरिटि का गठन किया, जिससे यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा पर बल दिया गया है। इसके अलावा, राज्य होमस्टे बुकिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना, जिससे ग्रामीण पर्यटन व स्थानीय रोजगार अवसर बढ़े। इन पहलों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पर्यटन अब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि आर्थिक अवसरों का स्रोत बना है। निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ पर्यटन-उद्योग और स्थानीय सेवा श्रमिकों के लिए रोजगार का नया मैदान खुला है।

मोदी-काल और विकास की पहल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय एवं राज्यों की नीतियों ने उत्तराखण्ड के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। 25 वर्षों में जब प्रदेश ने सिर्फ कुछ हजार हवाई यात्रियों को आकर्षित किया था, आज वह प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों को खींच रहा है।

2025 में पीएम मोदी ने उत्तराखण्ड के लिए 8,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की निवेश वृद्धि व रोजगार सृजन को सराहा है, यह कहते हुए कि "लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश निवेशित हो चुके हैं और 81,000 से अधिक रोजगार सृजित हो चुके हैं"। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि मोदी-काल की नीतियों व केंद्र-राज्य सहयोग ने उत्तराखण्ड के विकास को गति दी है। राज्य के हिल्स व वादियों में भी अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन व उद्योग का नया स्वर देखा जा रहा है।

निवेश-उद्योग एवं रोजगार की दिशा

धामी सरकार ने सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रही; उन्होंने निवेश व उद्योग को हिमालयी प्रदेश में भी स्थापित करने की दिशा में नवाचार किए हैं। प्रदेश ने 8,800 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्र-से सहायता मांगी है, जो ऊर्जा, आवास व बुनियादी ढांचे पर काम करेगी। साथ ही, कई पुल-ब्रिज, सड़क व अन्य बुनियादी परियोजनाएं बोरो द्वारा विकसित की जा रही हैं, जिससे पहाड़ों में बेहतर सम्पर्क व रोजगार का अवसर खुला है। इन सब प्रयासों ने रोजगार के नए अवसर भी बनाए हैं, खासकर पर्यटन, सेवा-क्षेत्र व स्थानीय व्यापार में। इस तरह, राज्य ने पारंपरिक कृषि व पर्यटन आधारित मॉडल से आगे बढ़कर नए उत्पादन-सेवा आयामों की ओर कदम बढ़ाया है, जहाँ युवाओं को स्वयं रोजगार सृजित करने का अवसर मिलता है।

नवाचार-प्रेरित पहलः दुग्ध व गौ-संवर्धन

उत्तराखण्ड ने हिमालय के परिदृश्य में भी कृषि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु विशेष नवाचार अपनाए हैं। धामी सरकार ने 'e-Rupi' डिजिटल भुगतान प्रणाली लॉन्च की, जिससे किसानों को सब्सिडी सीधे मिलेगी। राज्य ने नए फल-उद्यान व प्रौद्योगिकी आधारित कृषि नीतियाँ शुरू की हैं। गौ-संवर्धन व दुग्ध उत्पादन की दिशा में, राज्य ने स्थानीय होम-स्टे व पर्यटन के साथ जुड़ी डेयरी-क्लस्टर तैयार किए हैं। पर्यटन-दुग्ध मॉडल से स्थानीय ग्रामीणों की आय को विविधता मिली है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आय की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि हिमालयी क्षेत्र में उद्योग लगाने, युवाओं को रखा व रोजगार देने के लिए विशेष चुनौती है। लेकिन धामी सरकार ने इसे विकास का अवसर बना दिया है।

चुनौतियाँ और दृष्टिकोण

हिमालयी क्षेत्र की भूकंपीय व पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सावधानी आवश्यक है। पर्यटन वृद्धि ने भौतिक व सांस्कृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ाया है। निवेश व रोजगार सृजन की दिशा में सुनिश्चितता व निगरानी की जरूरत बनी हुई है उत्तराखण्ड सरकार को इन चुनौतियों से पार पाने हेतु सतत विकास, स्थानीय हिस्सेदारी व पारदर्शिता पर विशेष जोर देना होगा। धामी की प्रशासनिक शैली जिसमें उन्होंने मोर्चा संभाला है, इसमें भूमि-आधारित निवेश, स्थानीय युवाओं की भागीदारी और सेवा-उन्मुख रोजगार मॉडल प्रमुख हैं।

उत्तराखण्ड मॉडलः आत्मनिर्भरता और भविष्य की दिशा

पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में उत्तराखण्ड ने "विकास और विरासत" के संतुलन का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार ने यह समझा कि यदि पर्वतीय प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसकी नीतियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल समावेशन पर केंद्रित होनी चाहिए। इसी सोच के साथ राज्य में "स्टार्टअप उत्तराखण्ड" और "युवा स्वरोजगार मिशन" जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनके तहत हजारों युवाओं को प्रशिक्षण, ऋण और विपणन सहयोग मिला है। महिलाओं की भागीदारी भी इस विकास यात्रा का अभिन्न अंग बनी है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को न केवल वित्तीय सहयोग दिया गया, बल्कि उन्हें स्थानीय उत्पादों जैसे जैविक शहद, पर्वतीय मसाले, ऊनी वस्त्र और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर मिला। इसी के समानांतर, "वन उत्पाद आधारित उद्योग" नीति से कुमाऊँ और गढ़वाल के ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे उद्योग पनप रहे हैं। राज्य सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है।

लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगी आदर्श युवा ग्रामसभाएं

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी होती है। यह सुखद है कि विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या भारत में है। आधे नागरिक 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से वे इस युवा ऊर्जा को नावाचार से जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसमें सफलता भी मिली है। इसी का नतीजा है कि देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। अब युवा जनसांख्यिकीय ताकत को पंचायती राज में शिक्षित युवाओं के समावेशीकरण की दृष्टि से एक अनूठी नवाचारी पहल पंचायती राज मंत्रालय ने की है। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय और शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 'आदर्श युवा ग्रामसभा' यानी मॉडल यूथ ग्रामसभा (एमवायजीएस) एक ऐसी पहल है, जो युवाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी और नेतृत्व को प्रेरित करती है। ये युवा ग्रामों में जमीनी लोकतंत्र की भावना को न केवल मजबूती देंगे, अपितु त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल होकर नवीन डिजिटल माध्यमों से ग्राम पंचायत प्रशासन को पारदर्शी बनाने के साथ, उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम भी करेंगे। इस व्यवस्था को तीनों विभागों ने तालमेल बिठाकर 30 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ भी कर दिया है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष से कहीं ज्यादा संवैधानिक महत्व ग्राम सभाओं का है। हालांकि कमोबेश पूरे देश में ग्राम सभाओं को नजरअंदाज किया जाता है। कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी ग्राम सभाओं के कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रस्तावों को टाल देते हैं। ग्राम सभाओं की इस कानूनी बाध्यता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वेदांता जैसी खनिज उत्खनन की बहुराष्ट्रीय कंपनी और ओड़ीसा राज्य सरकार के मामले में 2013 में दिए गए एक फैसले से जानते हैं। शायद देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि पंचायत राज और ग्रामसभा के अधिकारों की कितनी अहम् भूमिका ग्राम विकास में अंतर्निहित है। पंचायत और वनाधिकार कानून की यह न्यायिक व्याख्या ऐसी राज्य सरकारों के लिए एक सबक है, जो इन कानूनों को ताक पर रखकर मनमानी करती हैं। इस दृष्टि से ओड़ीसा की नियमगिरी की पहाड़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बॉक्साइट के उत्खनन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। यहां गौरतलब है कि न्यायालय ने खुद व्यापार की कोई नई कानूनी संहिता नहीं रची थी, बल्कि अदालत ने पहले से ही प्रचलन में आए 'पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम' (पेसा) और आदिवासी एवं अन्य वनवासी भूमि अधिकार अधिनियम वनाधिकार कानून में तय मानदण्डों के आधार पर ही अपना फैसला दिया था। अदालत ने केवल यह रेखांकित किया था कि इन कानूनों के तहत आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय खनिज संपदाओं के उपयोग के संबंध में ग्रामसभाएं पूरी तरह अधिकार संपन्न हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई कंपनी या राज्य सरकार बेजा दखल नहीं दे सकती है। साथ ही, कार्यपालिका ग्रामसभा के निर्णय को मौके पर पालन कराने के लिए बाध्यकारी है। इस फैसले के बाद वेदांता समूह को मिले खनन के अधिकार पर ग्रहण लग गया था। इससे गांव में जमीन पर सामुदायिक हक किसका है, यह निर्धारित करने का निर्णय ग्राम सभाओं को मिल गया था। इससे पहले इसी आधार पर 2009 में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में खनन पर रोक लगा चुकी थी। ग्राम सभाओं के इसी महत्व को अंगीकार करते हुए कर्नाटक के बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्गा जिलों में लौह अयस्क उत्खनन के 50 पट्टे भी शीर्ष न्यायालय ने रद्द कर दिए थे। अदालत के इस लोकतांत्रिक एवं जनहितैषी कानून सम्मत फैसले से इस अवधारणा को शक्ति मिली थी कि जिन मूल निवासियों के संसाधनों पर परियोजनाएं स्थापित होनी हैं, उन्हें लगाने या न लगाने का अधिकार पंचायत अधिनियम में दर्ज ग्राम सभाओं को है। ग्राम सभाएं निर्णय लेने को पूरी तरह स्वतंत्र हैं। चूंकि आदर्श युवा ग्राम सभाओं में ऐसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत गतिविधि आधारित और अनुभवजन्य शिक्षा पर बल देती है। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य छात्रों में संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों के प्रति सम्मान के साथ देश के प्रति भावनात्मक जुड़ाव विकसित करना है। इसीलिए इन आदर्श युवा ग्राम सभाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और अन्य सरकारी विद्यालयों के नवीं एवं दसवीं के छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि यही संस्थान समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है। अतएव इस पहल का दायरा सभी ग्रामीणों से लेकर जनजातीय समुदाओं तक फैला हुआ है। चूंकि संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ इन समुदायों की महिलाओं को भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। इसीलिए ग्राम पंचायतों को भारत की विविधता का वास्तविक प्रतिबिंब माना जाता है। निश्चित ही यह लोक-कल्याणकारी निर्णय ग्रामीण जनसमूहों में चेतना का आधार बनेगा और ग्राम विकास में ग्राम सभा की भूमिका मजबूत होगी। साथ ही इस ऐतिहासिक फैसले के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों और उद्योगपतियों को यह संदेश लेने की जरूरत है कि वे अब अपेक्षाकृत ज्यादा मानवीय और समावेशी विकास की पक्षधर दिखें? तभी विकेंद्रीकृत पंचायती राज प्रणाली में कानून की सार्थकता सिद्ध होगी। युवाओं द्वारा स्वप्न देखना स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन प्रचार के जरिए देश में माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है कि सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी करना ही जीवन की सफलता है। परंतु यह प्रयोग प्रशिक्षित युवा वर्ग में निर्वाचन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लेने की उम्मीद जगाता है। यदि इन युवाओं को पर्याप्त अवसर मिलते हैं, तो उनमें पंचायती राज की कमियों को दूर करने की क्षमता तो दिखाई देगी ही, वे आलोचनात्मक सोच के माध्यम से चुनौतियों की पहचान कर उनके उचित समाधान के प्रति भी प्रतिबद्ध दिखाई देंगे। चूंकि ये शिक्षित होंगे, इसलिए समकालीन मुद्दों पर नई दृष्टि से विचार करेंगे और समाज को संवाद से प्रेरित करेंगे। अतएव कह सकते हैं कि युवा सरकारी नौकरी पाने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार एवं स्वालंबन का बड़ा आधार बनेंगे। पंचायती राज में इन युवाओं की भूमिका इसलिए भी अहम् रूप में रेखांकित होगी, क्योंकि अब वर्तमान नीतिगत तकनीकी उपायों और कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर से चलने वाले प्रशासन के जरूरी हिस्सा हो गए हैं। इनका सही इस्तेमाल निरीक्षण और अशिक्षित पंचायत प्रतिनिधि की बजाय सुशिक्षित एवं तकनीक का जानकार निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि कहीं ज्यादा कारगर एवं परिणाम मूलक उपयोग कर पाएंगे। अतएव आदर्श युवा ग्राम सभा एक रूपांतरणकारी दौर से गुजरेगी और इस स्थानीय शासन-प्रशासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे। भारत जब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में चल पड़ा है, तब पंचायती राज की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करना जरूरी हो जाता है।

किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सरगुजा, बस्तर सहित मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी।

गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के माध्यम प्रदेश में लगभग 01 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक

बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज सह उदवहन सिंचाई परियोजना, बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज सह उद्धवहन सिंचाई परियोजना, रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना, अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन निर्माण (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) कार्य, बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना, कुम्हारी जलाशय जल क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के अंतर्गत समोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य, दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा के सहगांव उद्धवहन सिंचाई योजना, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेय जल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना, जशपुर जिले के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्धवहन सिंचाई योजना की स्वीकृति

जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत वृहद परियोजना ऑगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्धवहन सिंचाई परियोजना, कोरबा जिले के अंतर्गत मड़वारानी बैराज निर्माण सह उदवहन सिंचाई योजना, गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना तथा बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना के बाएं तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्धवहन फीडर सिंचाई का निर्माण कार्य शामिल किया गया है।

जलवायु परिवर्तन से दुनिया के जंगलों में आग लगने का खतरा

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

पिछले कुछ दशकों में, जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का प्रमुख विषय बन गया है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि जंगल में आग लगने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, खासकर वे इलाके जो पहले तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाते थे। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न, अमेरिका के पश्चिमी हिस्से, और यूरोप के कुछ बड़े वनों में आग की घटनाएं अधिक रिकार्ड की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक, आज 20 साल पहले की तुलना में जंगलों में लगने वाली आग के कारण दोगुने से अधिक पेड़ नष्ट हो रहे हैं और मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। पृथ्वी की औसत सतह तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, समुद्र का बढ़ता स्तर, और अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि ये सभी जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। इन संकेतों के बावजूद, इस मुद्दे की गंभीरता और तात्कालिकता को समझने और प्रभावी कदम उठाने में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इस लेख में जलवायु परिवर्तन से उपजी जंगलों के जलने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा। हाल के वर्षों में, जंगल की आग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, लगातार और विनाशकारी हो गई है। दुनिया भर में, आग की लपटें जंगलों, घास के मैदानों और समुदायों को चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती हैं। धुएँ से पूरा इलाका धुँआ हो जाता है, आसमान नारंगी हो जाता है और हवा में साँस लेना खतरनाक हो जाता है। कई लोगों के लिए, जंगल की आग अब दुर्लभ आपदाएँ नहीं रह गई हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। इस बढ़ते खतरे का कारण कोई रहस्य नहीं है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग का आपस में गहरा संबंध है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को गर्म कर रहा है, जंगलों को सुखा रहा है और जंगल की आग के भड़कने और फैलने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शोध कहता है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तेजी से जारी रहा तो सदी के अंत तक दुनिया के लगभग 74% जंगलों में आग का खतरा रहेगा। यह स्थिति न केवल वन्य जीवन और जैव विविधता के लिए हानिकारक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कार्बन सोखने की हमारी क्षमता को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें एक और चिंता की बात यह है कि लगातार आग लगने से जंगल अब कार्बन को अवशोषित करने के बजाय उत्सर्जन का स्रोत बन सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर हो सकता है। जंगल में आग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवीय गतिविधियां होती हैं। प्राकृतिक कारण जैसे बिजली का गिरना (अक्सर सूखी जड़ों या झाड़ियों पर बिजली गिरने से आग शुरू होती है) और तेज हवा (तेज हवा आग को तेजी से फैलाती है) दूसरा कारण है मानवजनित कारण। इसके अंतर्गत आता है जानबूझकर या अनजाने में आग लगाना (शिफ्टिंग खेती, जंगल में घूमते समय लापरवाही, सीगरट या अलाव छोड़ देना)। और जंगल प्रबंधन में लापरवाही जैसे निस्तारण के लिए आग लगाना। एक और कारण है गैर-इंजीनियरी कारण जिसके अंतर्गत आता है टूटे बिजली के तार, सड़क किनारे स्पार्क, आदि। परंतु जलवायु परिवर्तन जैसे कि तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, लम्बी सूखा अवधि और मौसम के पैटर्न का बदलना जैसे घटनाओं को और अधिक गंभीर बना रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब जंगल की आग के क्षेत्र, अवधि और तीव्रता को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। इससे आग का मौसम अधिक लंबा हो गया है और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन से जंगल की आग न केवल बदतर होती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को और भी बदतर बना देती है। जब जंगल जलते हैं, तो वे वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह ग्रीनहाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जिससे और अधिक आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम जलवायु परिवर्तन से होने वाली जंगल की आग को और बदतर होने से रोकना चाहते हैं, तो हमें कई मोर्चों पर कदम उठाने होंगे। इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा और साथ ही जंगलों, ज़मीन और समुदायों के प्रबंधन के तरीके में भी बदलाव लाना होगा।

सेवानिवृत्तिः अनुभवी पारी का आग़ाज़; नई ऊर्जा और नये लक्ष्य के साथ करें नई शुरुआत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

शासकीय सेवाकाल में सेवानिवृत्ति की तारीख़ की गणना सेवा शुरूआत करने के दिन से ही शुरू हो जाती है। सारे लक्ष्य, सारे उसूल और सारे मापदंड को हम एक तारीख़ के साथ जोड़ देते है, जो कई बार नकारात्मक विचारों के साथ इसे सेवा का नहीं बल्कि ख़ुशियों का अंत दिखने लगता है। लेकिन हक़ीक़त इससे बिल्कुल परे है। सेवा निवृत्ति दर असल आपके दीर्घकालिक अनुभवों और हसरतों के साथ नये अध्याय को जोरदार शुरुआत का शंखनाद होती है। मैंने दो महान विभूतियों को खोया है, जिनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सेवानिवृत्ति के बाद ही शुरू हुआ। पहले डॉ. एमएल भाटी जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र राणापूर में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और पीड़ितों की सेवा और मानवता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल बनकर लोगों के दिलों में राज करते रहे। दूसरे रिटायर्ड डीएसपी एनएस जादौन जिन्होंने सैकड़ो बुजुर्गों की सेवा की, उन्हें कानूनी अधिकार दिलाए और समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। वे रिटायरमेंट के बात से अपने जीवन की अंतिम सांस तक बुजुर्गों की सेवा में लगे रहे। इन दोनों विभूतियों के कार्यों ने जहां मुझे गौरवान्वित किया, वहीं इनके अनंत यात्रा पर जाने ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि कैसे इन विभूतियों ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेकंड इनिंग समाज सेवा में खेली और ऐसी खेली कि उसे हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात हमें यह संदेश देती है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। आज हमें अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अपने अनुभव और ज्ञान से समाज में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं।

मैं सभी सेवानिवृत लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने जीवन की सेकंड इनिंग को समाज सेवा के लिए समर्पित करें। हमारे सभी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है। चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर हमारा ज्ञान और अनुभव। आइए मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। मैंने पुलिस और प्रशासन दोनों ही क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में मैं मेरे साथी जो कि अब सेवानिवृत हो चुके हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर समाज सेवा के कार्यों में जुटे और लोगों की सहायता करें पीड़ित मानवता को स्नेह प्रदान करें। हम सेवानिवृत्ति के बाद समाज को कई तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हैं। जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं-

- *युवाओं को मार्गदर्शनः अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को करियर मार्गदर्शन दे सकते हैं। विशेषकर उन युवाओं को जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं।*
- *सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमः स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।*
- *यातायात नियमों के बारे में जागरूकताः सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।*
- *अपराध रोकथाम कार्यक्रमः मोहल्लों में जाकर अपराध रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं।*
- *समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करनाः विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करके शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।*
- *स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होनाः विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होकर उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं।*
- *बुजुर्गों की देखभालः अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं।*
- *आपदा प्रबंधन में योगदानः आपदा के समय लोगों की मदद कर सकते हैं और राहत कार्य में भाग ले सकते हैं।*

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)